

Shri Sanjiva Reddy: Yes, Sir. I do not have the names. But I did say that that was one of the reasons.

Shri S. M. Banerjee: Will you ask the Minister to give the names, Sir? That was the question.

श्री हुकम चन्द कछवाय: इतना बड़ा काम सौंपा गया है और नाम भी नहीं बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: इस वक्त वह उनके पास नहीं है। अगर मैनबर साहिबान चाहें तो वह दे देंगे। इस में बड़ी अजीब बात क्या हो गई ?

Shri P. K. Deo: Since stainless steel is not produced in this country and since there is a great demand for imported steel for that purpose, may I know if there is any scheme to produce stainless steel in this Alloy Steel Project at Durgapur?

Shri P. C. Sethi: It will also be produced. About 18,000 tons of stainless steel will be produced there.

Shrimati Savitri Nigam: May I know how far this is correct namely, a lot of machinery of this type was manufactured here in our projects, and because of the lack of co-ordination, these plants and machinery have been ordered and a lot of foreign exchange is going to be spent unnecessarily?

Shri P. C. Sethi: This is not correct. This is as far as the machinery required for the special steel project is concerned. It is not possible to have it here and that is why it was ordered on a global basis.

श्री हुकम चन्द कछवाय: मैं जानना चाहता हूँ कि इस कार्य के लिये कितने ठेकेदारों ने टेंडर दिये थे और उन में सब से कम किस का था और सब से ज्यादा किस का था और कौन कौन से ठेकेदार थे ?

Shri P. C. Sethi: I want notice for this.

सीमेन्ट की कमी

+

* 37. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मानसिंह पू० पटेल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बुलेश्वर मीना :
श्रीमती रामबुलारी सिन्हा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के तारकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट की कमी को दूर करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): The Cement Corporation of India has been registered on 18-1-1965 as a private limited company fully owned by Government with an authorised capital of Rs. 5 crores. The new slag cement factory at Jamul has gone into production. An expansion scheme for an additional capacity of 100,000 tonnes of cement has been commissioned for full production at Panyam (Andhra Pradesh). Out of the existing 38 factories, production during 1964 at twenty factories has been higher than in the year 1963.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: संसद के पिछले अधिवेशन में इस प्रकार की चर्चा आई थी कि अश्लोत्पादन के लिये सिंचाई साधनों में इस लिये कमी रह गई है कि सीमेन्ट का अभाव है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस दिशा में भी कोई प्रयास किये हैं कि कृषि साधनों के विकास के लिये उनको उन की

प्रावश्यकता के अनुरूप पूरा सीमेंट मिल सके ।

Shri Bibudhendra Misra: Yes, Sir; Production is rising and naturally that will be done.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था ।

Mr. Speaker: He wants to know whether measures have been taken so that people may get cement for irrigation needs.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंचीनिर्धारण तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : सीमेंट की कमी है लेकिन ज्यों ज्यों पूर्ति होती जा रही है उस में से प्रयत्न यह होता है कि कृषि आदि के लिये ज्यादा हिस्सा दिया जाये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आज यह कहने की स्थिति में है कि इतने समय से सीमेंट का जो अभाव देश में चल रहा है वह कितने समय तक पूरा हो जायेगा और उस के बाद देश में सीमेंट की कमी नहीं रहेगी ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरा यह अनुमान है कि अगर सीमेंट कारपोरेशन की प्लैन और प्राइवेट सेक्टर की प्लैन तेजी से बढ़ती जायेंगी तो करीब करीब तीन वर्ष के अन्दर इस मामले को हल कर लिया जायेगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : चूँकि सीमेंट के कारखाने वाले सरकार की मदद से कारखाने के पास पास की जमीन को ले लेते हैं और उन के करार की शर्तों को पूरा नहीं करते लोगों को मुआवजा नहीं देते तो यह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है या राज्य सरकारों का । यदि राज्य सरकारों का है तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बाधित करेगी कि वे शर्तों को पूरा करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सिर्फ सीमेंट के लिब्रे ले लेते हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : किसी भी काम के लिये जमीन ले ली जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यह जनरल क्वेश्चन है और इस वक्त नहीं लिया जा सकता ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : किसानों को जमीन का मुआवजा तो मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जनरल क्वेश्चन है और आप इस को प्रेजिडेंट्स ऐड्रेस के समय ले सकते हैं ।

Shri Man Sinh P. Patel: In view of Government's inability to reach the target for cement laid down in the third plan and in view of the new sanctions, I want to know whether Government will be in a position to improve the availability of cement in the current two years to meet the irrigation demand?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): There is no question of exclusive responsibility of Government in this case. It is a private sector industry mostly up till now. Many of the private plants for which licences have been given have not come up. That is one reason for the shortage. To make good the deficiency, Government have been compelled to start the Cement Corporation which will take care of public sector undertakings to be started.

Shri S. C. Samanta: May I know whether a material called Pozzolene which was available near about Bhakra Dam has been tried in place of cement?

Shri Bibudhendra Misra: Yes Sir. As a matter of fact, some new licences have been given recently. I cannot give the exact places. But one has been given at Rajgangpur, so far as I remember.

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के पास इस तरह का कोई भ्रकारंट है कि इस की

कितनी डिमांड है और सप्लाय में कितनी कमी रहती है। सप्लाय में जितनी कमी रहती है उस के फिगरिंग क्या सरकार इस सदन की मेज पर रख सकती है।

Shri Bibudhendra Misra: The demand today is 12 million tonnes per annum and the supply is about 10 million tonnes. There is a shortfall of 2 million tonnes.

Shrimati Savitri Nigam: What precautions have Government taken to ensure that private sector people will not let them down and to enable them to fulfil the target?

Shri Bibudhendra Misra: As already stated, Sir, we have formed the Cement Corporation of India with that end in view.

Shri P. R. Patel: How is it that big firms get cement for construction of buildings in cities whereas the poor cultivators do not get cement for wells and other irrigation facilities?

An hon. Member: They cannot pay the blackmarket price.

Shri T. N. Singh: We allot cement to the States who distribute it. We do not distribute cement direct in the States from the Centre.

श्री प्र० सि० सहगल : कितनी दुर्वास्तों प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सीमेंट के कारखाने खोलने के लिये ग्राप के पास ग्राई हैं दूसरे पब्लिक सेक्टर में ग्राप ने क्या तजवीज की है कि कितने कारखाने चौथी प्लेन में ग्राप खोलेंगे।

श्री त्रि० ना० सिंह : यह कहना तो मुश्किल है क्योंकि ऐप्लिकेन्टस की पूरी लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है। जहां तक गवर्नमेंट कारपोरेशन का सम्बन्ध है हम लोग कई स्थानों पर सीमेंट लाइम स्टोन के बारे में जांच कर रहे हैं और जांच हो जाने के बाद इस के लिये प्रोग्राम बनेगा।

Shri Jashvant Mehta: Recently a meeting was convened of the licensees

to whom licences have been granted for cement production. May I know in the case of how many licences, even though they were granted two years back, the licensees have not still started any preparation for cement production? May I also know what is the latest position regarding the new licences that have been issued?

Shri Bibudhendra Misra: Sir, I could not follow the question.

Mr. Speaker: He wants to know the number of licensees who have not utilised the licences granted to them.

Shri Bibudhendra Misra: For that he may table a separate question.

श्री बृजराज सिंह : जब तक सीमेंट की कमी है और सरकार यह देख रही है कि काश्तकार की छोटी प्रोजेक्ट्स के लिये सीमेंट काफी नहीं है तब तक क्या गवर्नमेंट यह उचित नहीं समझती कि नेताओं के मकबरो और कब्रिस्तानों में जो सीमेंट इस वक्त खर्च किया जा रहा है वह रोका जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ मुद्दों की मिट्टी उतारने से ही सारा मसला हल हो जायेगा।

श्री बृजराज सिंह : मुद्दों के पेट में डालने से भी तो मसला हल नहीं होगा।

Shri S. M. Banerjee: In reply to a question the hon. Minister stated that distribution is made by the State Governments. I would like to know whether the shortage has been accentuated by the mal-distribution or wrong distribution by the State Governments; if so, may I know what is the machinery with the Central Government to check that the distribution is done in a fair and proper manner?

Shri T. N. Singh: I would say that the States are doing the best that lies in their capacity to distribute it in a fair and equitable manner. I am not here to sit in judgment over them.

श्री टा० ना० तिबारी: अभी सरकार की तरफ से उत्तर आया कि बहुत से प्राइवेट

सेक्टर के लोगों ने लाइसेंस ले कर सीमेंट की फैक्ट्रियां इस्टैब्लिश नहीं कीं। तो क्या सरकार उन जगहों में जहां पर कि प्राइवेट पार्टीज इस्टैब्लिश करना चाहती थीं गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर में सीमेंट फैक्ट्रियां इस्टैब्लिश नहीं कर सकती।

Shri Bibudhendra Misra: Yes, Sir, some licences have been cancelled because the parties did not start the factories. The Government would make a study of all that with the help of the Cement Corporation.

Shri D. N. Tiwary: My question was whether in those places where the licences have been cancelled the Government would consider the desirability of establishing factories in the public sector.

Shri Bibudhendra Misra: The Cement Corporation will consider that if no private parties are forthcoming.

Dr. M. S. Aney: In view of the shortage of cement, the inadequacy of the supply of cement and the growing demand of the people for cement, is the Government making any endeavour to bring into working all the quarries where cement is available?

Shri Bibudhendra Misra: Our average utilisation of capacity is about 93 per cent. But there are factories which are working up to hundred per cent.

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात सच नहीं है कि सरकार की यह योजना कि सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्रियां खोली जाएं, इस लिए है कि जितने भी लाइसेंस निजी क्षेत्र में दिए गए उन में से एक ने भी फैक्टरी नहीं बनायी? अगर यह बात सच है तो सरकार आज फिर इस दुसमूल नीति को पालन करने के लिए उनको सीमेंट बनाने का काम क्या देना चाहती है, क्यों स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र में इस काम को नहीं करती है?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी बात नहीं है कि वे बिल्कुल फेल कर गए हैं। उनमें से कुछ ने फैक्ट्रियां लगायी हैं और बढ़ायी हैं।

श्री भागवत झा आजाद : पिछले पांच साल में एक ने भी नहीं बनायी है।

श्री गुलशन : कहा गया कि कृषि निर्माण के लिए सीमेंट दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान को जो सीमेंट की जरूरत है क्या वह भी सरकार के नोटिस में है?

अध्यक्ष महोदय : एक एक स्टेट के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघानी : क्या सरकार ने सीमेंट के राजकीय प्रतिष्ठान स्थापित करने के बारे में सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि ये राजकीय प्रतिष्ठान उन स्थानों पर ही स्थापित किए जायेंगे जहां चूना और जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि जिन स्थानों पर चूना और जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां यह उद्योग स्थापित नहीं किए गए।

श्री त्रि० ना० सिंह : प्रश्न समझ में नहीं आया।

Mr. Speaker: Now the question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

State Trading Corporation

*32. { **Shri Prabhat Kar:**
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration to expand the activities of State Trading Corporation; and